

अवश्यभावी है। मैं केन्द्रीय कांग्रेसी शासकों से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय माननीय अशोक मेहता के साथ बहुत से सोशलिस्ट कांग्रेस में आये थे, उनका स्वागत क्यों किया गया था? क्यों नहीं उनसे कहा गया था कि वे अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर, कांग्रेस के चुनाव-चिन्ह पर लड़कर जनता का विश्वास प्राप्त तो यह दल बदल बाद की नयी परम्परा किसने चलाई? देश में या हमारे देश की राजनीति में यह जहर और विष कौन फँला रहा है? इसी प्रकार से देश की अन्य पार्टियों से इक्का टुकका लोग जब कांग्रेस में शामिल हुए तो उनका स्वागत क्यों किया गया, क्यों नहीं उनसे इस बात का आग्रह किया गया कि वे जिन पार्टियों से चुनाव जीत कर आये हैं उनसे इस्तीफा दें और फिर कांग्रेस के टिकट पर अपने बहुमत का अंदाजा लगाकर विधान सभा या लोक सभा में आयें? तो यह नयी परम्परा, कु-परम्परा कांग्रेस ने डाली है, उसका असर अन्य पार्टियों पर पड़ना अवश्यभावी है।

मान्यवर, जो प्रेसीडेंट रूल हमारे उत्तर प्रदेश में लागू किया गया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वहाँ पर स्पष्ट बहुमत संविद का पहले भी था और आज भी है। इसलिए यह जो नया चक्र चलाया गया है उससे हमारे प्रदेश का नुकसान हुआ है। जो वहाँ पर नग्न नौकरशाही शासन का तांडत्व-नृत्य-हो रहा है उसमें जन-प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं रह गया है उनके स्थान पर सेक्रेटरी रूल कायम हो गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ पर प्रेसीडेंट रूल जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। वहाँ पर विधान सभा को बुलाकर अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि संविद का बहुमत है अथवा नहीं। वहाँ की किसी भी पार्टी ने न तो गवर्नर को इस बात की सूचना दी और न राष्ट्रपति को ही सूचना दी कि वह संविद में नहीं है। संविद की सरकार में भले ही कोई पार्टी शामिल हो अथवा न हो परंतु सभी

पार्टियां संविद के साथ थीं और आज भी हैं। सरकार में जाना और संविद में रहना, यह दोनों एक समान और पर्यायवाची चीजें नहीं हैं। कोई भी पार्टी, संविद में रह सकती है लेकिन सरकार में नहीं रह सकती है। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी संविद सरकार से अलग हो गई, सोशलिस्ट पार्टी संविद सरकार से अलग हो गई लेकिन दोनों पार्टियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वे संविद के साथ हैं और संविद सरकार का समर्थन करती रहेंगी।

ऐसी स्थिति में कोई भी औचित्य नहीं है जोकि वहाँ पर प्रेसीडेंट रूल कायम किया गया है।

16. Hrs.

मान्यवर, केन्द्रीय कांग्रेसी शासक अगर इस तरीके से हिन्दुस्तान में प्रतिक्रिया चलायेंगे तो उस का खमियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा और पूरे देश की जनता को हानि उठानी पड़ेगी। उस का कारण यह है कि हमारे देश में दो ही बात चल सकती है, या तो प्रजातंत्र चले या कोई दूसरा तंत्र चले। दो ही भाषा बोली जा सकती है, या तो प्रजातंत्र की...

Mr. SPEAKER : He may continue next time.

16.01 Hrs.

#### COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

##### TWENTY-FOURTH REPORT

श्री हरदयाल देबगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करना हूँ कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24वें प्रतिवेदन से, जो 20 मार्च, 1968 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House agrees with the Twenty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolu-

[Mr. Speaker]

tions presented to the House on the 20th March, 1968."

*The motion was adopted.*

16.02 Hrs.

**RESOLUTION RE ACTIVITIES OF LEFT COMMUNIST PARTY—contd.**

**SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) :** On the 8th March, 1968, when the ill-conceived and wrongly worded Resolution of my learned friend, Shri Prem Chand Verma, was moved in this House I raised a point of order and when I was developing it the hon. Deputy-Speaker adjourned the House.

I may invite your kind attention and, through you, the attention of hon. Members to the wording of the Resolution. The Resolution reads :

"This House is of opinion that the Left Communist Party of India be declared unlawful as its activities have posed a danger to the unity, integrity and security of the country."

These are the two aspects of the Resolution.

My first objection to this is that there is no party in the country known as the Left Communist Party of India.

**SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) :** Then, why are you worried ?

**SHRI S. M. BANERJEE :** This House cannot discuss anything in abstract. Suppose, I say, instead of Prem Chand Verma Ghriana Chand Verma, will he accept it ? He will never accept it. His name is Prem Chand Verma and he can call himself either P. C. Verma or Prem Chand Verma, not anything else. This Resolution says, "the Left Communist Party of India."

Then, I draw your attention to rule 186. It says :

"In order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely :—

it shall raise substantially one definite issue ;

it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations or defamatory statements ;

it shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity :

it shall be restricted to a matter of recent occurrence ;

it shall not raise a question of privilege ;"

and so on.

Then, Rule 173 clearly says :

"It shall be clearly and precisely expressed ;"

Now, I have before me the Manual of Election Law, 5th Edition. What does it say ? It says :

"Multi-State Party means any of the following recognised parties, namely, the Indian National Congress . . . .

—it has become anti-national—

"...the Swatantra Party, the Communist Party of India, the Communist Party of India (Marxist), the Bhartiya Jana Sangh, the Praja Socialist Party, the Samyukta Socialist Party, the Republican Party of India in relation to such and such symbols."

According to the Election Manual, one Party fought elections along with others called the Communist Party of India (Marxist). They call themselves Marxists and Leninists. But it has been accepted as Marxist. What I say is we cannot discuss in this House anything in abstract.

**MR. SPEAKER :** Your point is clear ; make it short.

**SHRI S. M. BANERJEE :** I am coming to that. I am not concerned with other ironical expressions which have been very well covered by my hon. friend, Shri H. N. Mukerjee. I am concerned only with this : Can this House discuss a Resolution like this ? The Resolution, if it is amended, can be as follows :

"This House is of the opinion that those who left the Communist Party of India be banned."

That amendment can be accepted. But under no circumstances this Resolution, as it is, should be admitted.

Sir, I seek your guidance and I appeal to your sense of justice and impartiality not because of any other reason. They may move thousand Resolutions. We are not concerned with that ; they have the right